भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्नि संख्याय 3798

16 जुलाई, 2019 के लिए प्रश्न

चीनी उद्योग के समक्ष समस्याएं

3798. श्री दयानिधि मारन:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में चीनी उद्योग ने इस बात की ओर संकेत किया है कि सरकार की सहायता योजनाएं पूर्ण रूप से अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों पर केन्द्रित हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारात्मक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या गन्ना उत्पादन में कमी के कारण तमिलनाडु में मिलों को निम्न क्षमता के उपयोग (35%) की अजीब स्थिति का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या ये मिलें चीनी का निर्यात नहीं कर सकती हैं, क्योंकि चीनी का उत्पादन (8.5 लाख टन) राज्य की घरेलू आवश्यकताओं (18 लाख टन) को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति के लिए किन कारणों को चिन्हित किया गया है; और

(ङ) क्या यह सच है कि पांच वर्ष पूर्व तमिलनाडु देश का तीसरा या चौथा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य था, जहां वार्षिक रूप से 23 लाख टन का उत्पादन होता था, लेकिन अब इसका चीनी उत्पादन घटकर सिर्फ एक तिहाई रह गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है?

उत्तधर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्यि मंत्री

(श्री दानवे रावसाहेब दादाराव)

(क): चीनी क्षेत्र के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा तैयार की गई सहायता स्कीमें देश में सभी चीनी उत्पादक राज्यों के लिए एकसमान तरीके से लागू हैं। तमिलनाडु सरकार ने चीनी क्षेत्र की राज्य विशिष्ट समस्याओं के बारे में अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है।

(ख) से (घ): वर्षा न होने की वजह से राज्य में पड़े सूखे और भीषण जल संकट के कारण गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र और प्रति हेक्टेयर पैदावार में गिरावट आई है। इसके परिणामस्वरूप गन्ने की उपलब्धता में कमी आई है, क्षमता उपयोग कम हुआ है और चीनी मिलों द्वारा चीनी के उत्पादन में कमी आई है।

(ड.): चीनी मौसम 2011-12 के दौरान तमिलनाडु में चीनी का उत्पादन 23.79 लाख टन था और यह चीनी का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य था। तथापि, उपर्युक्त भाग 'घ' के उत्तहर में उल्लिखित कारणों से वर्तमान चीनी मौसम 2018-19 के दौरान चीनी का उत्पादन घटकर 7.24 लाख टन रह गया है। केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-वाणिज्यिक फसलें (एनएफएसएम-सीसी) के तहत उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए गन्ने संबंधी फसल विकास कार्यक्रम अनुमोदित किया है। दिनांक 30.04.2019 की स्थि ति के अनुसार एनएफएसएम - (सीसी) गन्ने के तहत तमिलनाडु को वर्ष 2014-15 से केंद्रीय हिस्से के रूप में 204.11 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं।

******